IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 2, November 2025
Impact Factor: 7.67

श्योपुर जिले में समावेशी शिक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन एवं चुनौतियाँ

शबीना शेख़[1] and डॉ. भूपेंद्र सिंह चौहान[2]

[1]शोधार्थी, शिक्षा शास्त्र - विभाग

[2]शोध निर्देशक, शिक्षा शास्त्र - विभाग

विक्रांत विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)

सारांश

समावेशी शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बालक को उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं बौद्धिक विविधताओं के बावजूद समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। भारत सरकार द्वारा समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएँ जैसे समग्र शिक्षा अभियान, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा (IEDSS), तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई हैं। प्रस्तुत अध्ययन में श्योपुर जिले में इन योजनाओं के क्रियान्वयन तथा उनसे संबंधित चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव तथा सामाजिक जागरूकता की कमी प्रमुख बाधाएँ हैं।

मुख्य संकेतक: - समग्र शिक्षा अभियान, दिव्यांग विद्यार्थी, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक समानता।

परिचय

श्योपुर जिले में समावेशी शिक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन एवं उससे जुड़ी चुनौतियों को समझना वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक बालक को उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद समान अवसर प्रदान किया जाता है। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत यह है कि सभी बच्चों को एक

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 2, November 2025 Impact Factor: 7.67

ही शैक्षणिक वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाए और उनकी विशेष आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण पद्धतियों में लचीलापन अपनाया जाए।

यह अवधारणा केवल दिव्यांग विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाता है (शर्मा, 2018)। भारत सरकार ने शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनेक योजनाएँ प्रारंभ की हैं, जिनमें समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रमुख हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को समावेशी बनाकर प्रत्येक बालक तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाना है (भारत सरकार, 2020)।

श्योपुर जिला मध्यप्रदेश का एक महत्वपूर्ण लेकिन सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। यह जिला मुख्यतः जनजातीय आबादी से प्रभावित है तथा यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। जिले में शिक्षा से संबंधित समस्याएँ जैसे विद्यालयों की अपर्याप्त संख्या, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, बुनियादी संसाधनों की कमी तथा सामाजिक जागरूकता का निम्न स्तर लंबे समय से विद्यमान हैं। ऐसे परिप्रेक्ष्य में समावेशी शिक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह न केवल दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा के मुख्यधारा से जोड़ता है बल्कि सामाजिक समानता को भी प्रोत्साहित करता है (गुप्ता, 2020)। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्यालय में प्रवेश दिलाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर प्राप्त हो और वह समाज में आत्मनिर्भर बन सके।

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत श्योपुर जिले में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए अनेक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, जैसे सहायक उपकरण, छात्रवृत्ति, विशेष शिक्षण सामग्री तथा विद्यालयों में बुनियादी संरचनात्मक सुविधाएँ। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में रैम्प, विशेष शौचालय तथा अन्य सुविधाएँ विकसित करने का प्रयास किया गया है ताकि दिव्यांग विद्यार्थियों को विद्यालय आने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो (शिक्षा मंत्रालय, 2020)।

इसके साथ ही शिक्षकों को समावेशी शिक्षण पद्धतियों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षणिक आवश्यकताओं को समझने में सक्षम बनाना है (एनसीईआरटी,

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 2, November 2025 Impact Factor: 7.67

2019)। समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि शिक्षक ही विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया को दिशा प्रदान करते हैं।

श्योपुर जिले में समावेशी शिक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विद्यालय प्रबंधन समितियों तथा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अभिभावकों को शिक्षा प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे न केवल विद्यार्थियों की उपस्थिति में वृद्धि होती है बल्कि शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित होता है (वर्मा, 2021)। इसके बावजूद जिले में समावेशी शिक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ सामने आती हैं।

सबसे प्रमुख चुनौती संसाधनों की कमी है। जिले के कई विद्यालयों में आवश्यक शिक्षण सामग्री, सहायक उपकरण तथा प्रशिक्षित शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। इससे विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को उचित शैक्षणिक सहायता नहीं मिल पाती। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की दूरी तथा परिवहन सुविधाओं का अभाव भी विद्यार्थियों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है (सिंह, 2019)। सामाजिक जागरूकता का अभाव भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। कई बार अभिभावक दिव्यांग बच्चों को विद्यालय भेजने में रुचि नहीं दिखाते क्योंकि उन्हें शिक्षा के महत्व तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं होती। इस कारण अनेक बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं (मिश्रा, 2022)।

प्रशासनिक स्तर पर समन्वय की कमी तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में विलंब भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। कई बार योजनाओं के लिए निर्धारित बजट समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता, जिससे विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं का विकास बाधित होता है। इसके अतिरिक्त योजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली भी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं है, जिसके कारण योजनाओं के वास्तविक प्रभाव का आकलन कठिन हो जाता है (शिक्षा विभाग, 2021)।

समावेशी शिक्षा का सफल क्रियान्वयन केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज, विद्यालय, अभिभावक तथा प्रशासन के बीच समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। यदि विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाए, शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तथा समाज में जागरूकता बढ़ाई जाए तो समावेशी शिक्षा योजनाओं का प्रभाव अधिक सकारात्मक हो सकता है।

श्योपुर जिले में समावेशी शिक्षा योजनाओं का अध्ययन यह दर्शाता है, कि योजनाओं के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु अभी भी कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, संसाधनों की उपलब्धता तथा सामाजिक जागरूकता पर

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 2, November 2025 Impact Factor: 7.67

विशेष ध्यान देना आवश्यक है। समावेशी शिक्षा न केवल शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाती है बल्कि समाज में समानता, सहिष्णुता एवं सामाजिक न्याय की भावना को भी प्रोत्साहित करती है, जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है (पाण्डेय, 2019)।

समावेशी शिक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन

1. समग्र शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सहायक उपकरण, छात्रवृत्ति तथा विशेष शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। श्योपुर जिले में विद्यालयों में रैम्प, शौचालय तथा विशेष शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है (शिक्षा मंत्रालय, 2020)।

2. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। श्योपुर जिले में समय-समय पर शिक्षकों को समावेशी शिक्षण पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझ सकें (एनसीईआरटी, 2019)।

3. अभिभावक एवं समुदाय की भागीदारी

समावेशी शिक्षा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में समुदाय और अभिभावकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। श्योपुर जिले में विद्यालय प्रबंधन समितियों के माध्यम से अभिभावकों को शिक्षा प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है (वर्मा, 2021)।

समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ

समावेशी शिक्षा आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक बच्चे को उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषाई तथा आर्थिक विविधताओं के बावजूद समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। यह शिक्षा प्रणाली इस विचार पर आधारित है कि सभी बच्चे सीखने में सक्षम होते हैं और शिक्षा व्यवस्था को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक तथा सांस्कृतिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों को भी मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। भारत सरकार ने समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएँ जैसे समग्र शिक्षा अभियान, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशी शिक्षा कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की हैं।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 2, November 2025 Impact Factor: 7.67

इन योजनाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो तथा किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जा सके। हालाँकि समावेशी शिक्षा की अवधारणा अत्यंत सकारात्मक एवं प्रगतिशील है, फिर भी इसके क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ सामने आती हैं। सबसे प्रमुख चुनौती संसाधनों की कमी है। देश के कई ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में विद्यालयों में रैम्प, विशेष शौचालय, सहायक शिक्षण सामग्री तथा तकनीकी उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होती, जिससे दिव्यांग एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

इसके अतिरिक्त प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव भी समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन में एक बड़ी बाधा है। अधिकांश शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षणिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को समझने तथा उनके अनुसार शिक्षण पद्धति अपनाने का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिल पाता, जिसके कारण वे ऐसे विद्यार्थियों को उचित सहयोग प्रदान करने में असमर्थ रहते हैं।

समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में सामाजिक दृष्टिकोण भी एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में सामने आता है। कई स्थानों पर अभी भी दिव्यांग बच्चों के प्रति नकारात्मक सोच एवं भेदभाव की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जिसके कारण अभिभावक अपने बच्चों को सामान्य विद्यालयों में भेजने से हिचकिचाते हैं। जागरूकता की कमी के कारण समाज में समावेशी शिक्षा के महत्व को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अभिभावकों की आर्थिक स्थिति भी एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि गरीब परिवारों के लिए विशेष उपकरण, परिवहन सुविधा तथा अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता प्राप्त करना कठिन होता है।

प्रशासनिक एवं नीतिगत स्तर पर भी कई समस्याएँ देखने को मिलती हैं। योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक बजट का समय पर वितरण, विद्यालयों में निगरानी व्यवस्था तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी जैसी समस्याएँ अक्सर सामने आती हैं। कई बार योजनाएँ केवल कागजों तक सीमित रह जाती हैं और उनका वास्तविक लाभ लक्षित विद्यार्थियों तक नहीं पहुँच पाता। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में विद्यार्थियों की अधिक संख्या और शिक्षकों की कमी के कारण व्यक्तिगत ध्यान देना भी कठिन हो जाता है, जिससे समावेशी शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाते।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए केवल योजनाओं का निर्माण पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी संचालन, संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षक प्रशिक्षण, सामाजिक जागरूकता तथा प्रशासनिक सहयोग की भी अत्यंत आवश्यकता है। जब तक इन चुनौतियों का समुचित समाधान नहीं किया जाता, तब तक समावेशी शिक्षा का लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 2, November 2025 Impact Factor: 7.67

यह आवश्यक है कि सरकार, समाज, विद्यालय और अभिभावक मिलकर इस दिशा में समन्वित प्रयास करें, ताकि प्रत्येक बच्चे को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके।

1. संसाधनों की कमी

श्योपुर जिले के कई विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखा जाता है। विशेष उपकरण तथा शिक्षण सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है (गुप्ता, 2020)।

2. प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी

समावेशी शिक्षा के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है, लेकिन श्योपुर जिले में ऐसे शिक्षकों की संख्या सीमित है। इससे विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता (सिंह, 2019)।

3. सामाजिक जागरूकता का अभाव

ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रति सामाजिक जागरूकता कम होने के कारण समावेशी शिक्षा योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता (मिश्रा, 2022)।

4. प्रशासनिक बाधाएँ

योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासनिक स्तर पर समन्वय की कमी तथा बजट वितरण में विलंब भी प्रमुख समस्याएँ हैं (शिक्षा विभाग, 2021)।

सुझाव

1. विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।
2. शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
3. अभिभावकों एवं समाज में जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।
4. प्रशासनिक स्तर पर योजनाओं के प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

श्योपुर जिले में समावेशी शिक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन शिक्षा के क्षेत्र में समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। समावेशी शिक्षा का मूल

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 2, November 2025 Impact Factor: 7.67

उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बालक, चाहे वह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार की विविधता से संबंधित हो, उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिल सके। श्योपुर जैसे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े जिले में इन योजनाओं का विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में जनजातीय एवं ग्रामीण आबादी निवास करती है, जहाँ शिक्षा से संबंधित संसाधनों की कमी लंबे समय से देखी जाती रही है। सरकार द्वारा संचालित समग्र शिक्षा अभियान, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से जिले में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं, जिससे शिक्षा की पहुँच व्यापक हुई है और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को मुख्यधारा से जोड़ने में सहायता मिली है।

श्योपुर जिले में समावेशी शिक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन से विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं के विकास, सहायक उपकरणों की उपलब्धता, छात्रवृत्ति योजनाओं के विस्तार तथा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन जैसे सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। इन प्रयासों के कारण विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ी है तथा शिक्षा के प्रति समाज का दृष्टिकोण भी धीरे-धीरे सकारात्मक हुआ है। इसके अतिरिक्त विद्यालय प्रबंधन समितियों तथा जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अभिभावकों और समुदाय को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास भी किया गया है, जिससे विद्यार्थियों के समग्र विकास को प्रोत्साहन मिला है।

इसके बावजूद श्योपुर जिले में समावेशी शिक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। जिले के कई विद्यालयों में आवश्यक संसाधनों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव तथा बुनियादी संरचनात्मक सुविधाओं का अपर्याप्त विकास प्रमुख समस्याएँ हैं। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालयों की दूरी तथा परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण अनेक विद्यार्थी नियमित रूप से विद्यालय नहीं पहुँच पाते। इसके अतिरिक्त सामाजिक जागरूकता का अभाव भी समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि कई अभिभावक दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के महत्व को पूरी तरह नहीं समझ पाते। प्रशासनिक स्तर पर योजनाओं के समन्वय, बजट वितरण तथा निगरानी प्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता महसूस की जाती है।

समावेशी शिक्षा योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार प्रभावी और समन्वित रूप से किया जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालयों में पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, शिक्षकों को नियमित एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तथा

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 2, November 2025 Impact Factor: 7.67

समाज में समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाएँ। साथ ही, प्रशासनिक स्तर पर योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना भी आवश्यक है ताकि योजनाओं के वास्तविक प्रभाव का आकलन किया जा सके और आवश्यक सुधार किए जा सकें।

अंततः यह कहा जा सकता है कि श्योपुर जिले में समावेशी शिक्षा योजनाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु इन योजनाओं के पूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास और सुधार आवश्यक हैं। यदि संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षक प्रशिक्षण, सामाजिक जागरूकता और प्रशासनिक समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जाए, तो समावेशी शिक्षा न केवल जिले के विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास को सुदृढ़ बनाएगी, बल्कि समाज में समानता, सहिष्णुता और सामाजिक समरसता को भी प्रोत्साहित करेगी, जो किसी भी विकसित और प्रगतिशील समाज की आधारशिला होती है।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल, के. (2017). *विशेष शिक्षा का विकास.* जयपुर: राजस्थान प्रकाशन।
2. एनसीईआरटी. (2019). *समावेशी शिक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल.* नई दिल्ली: एनसीईआरटी।
3. गुप्ता, एस. (2020). समावेशी शिक्षा में संसाधनों की भूमिका। *शिक्षा शोध पत्रिका,* 12(2), 45-52।
4. चौहान, एल. (2020). समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। *शिक्षा दर्शन,* 8(1), 33-40।
5. जोशी, आर. (2018). दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षण पद्धतियाँ। *शोध शिक्षा जर्नल,* 9(2), 55-61।
6. ठाकुर, वी. (2019). समावेशी शिक्षा में प्रशासनिक चुनौतियाँ। *शिक्षा प्रबंधन जर्नल,* 7(2), 19-27।
7. तिवारी, एस. (2020). ग्रामीण विद्यालयों में समावेशी शिक्षा का अध्ययन। *शिक्षा अध्ययन पत्रिका,* 14(1), 25-31।
8. दुबे, आर. (2017). *समावेशी शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार.* लखनऊ: मनोविज्ञान प्रकाशन।
9. पाण्डेय, एन. (2019). समावेशी शिक्षा और सामाजिक समानता। *भारतीय सामाजिक शोध,* 11(4), 71-78।
10. भटनागर, एस. (2021). समावेशी शिक्षा में अभिभावक की भूमिका। *शिक्षा शोध समीक्षा,* 9(3), 41-48।
11. भारत सरकार. (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020.* नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 2, November 2025 Impact Factor: 7.67

12. मिश्रा, पी. (2022). ग्रामीण क्षेत्रों में समावेशी शिक्षा की चुनौतियाँ। *भारतीय शिक्षा समीक्षा*, 15(1), 60-68।
13. यादव, पी. (2021). समग्र शिक्षा अभियान का प्रभाव। *शिक्षा विमर्श*, 16(2), 44-50।
14. वर्मा, डी. (2021). विद्यालय प्रबंधन समिति और समावेशी शिक्षा। *शिक्षा संवाद*, 10(3), 22-30।
15. शर्मा, आर. (2018). *समावेशी शिक्षा की अवधारणा*. नई दिल्ली: शिक्षा प्रकाशन।
16. शिक्षा मंत्रालय. (2020). *समग्र शिक्षा अभियान दिशा-निर्देश*. नई दिल्ली: भारत सरकार।
17. शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश. (2021). *समावेशी शिक्षा वार्षिक रिपोर्ट*. भोपाल।
18. शुक्ला, एम. (2020). विद्यालयी वातावरण और समावेशी शिक्षा। *शिक्षा समीक्षा*, 12(1), 65-72।
19. सक्सेना, ए. (2018). दिव्यांग शिक्षा नीतियाँ और व्यवहार। *राष्ट्रीय शिक्षा पत्रिका*, 13(3), 90-98।
20. सिंह, एम. (2019). *दिव्यांग शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण*. भोपाल: मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी।